समक्ष एस. एस. संधावालिया, सी. जे. और एस. एस. दीवान, जे.

श्री चंद और अन्य - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. **1977** *का* **3365**

18 अगस्त, 1978

हरियाणा भू-जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम (1976 का 40 और 1978 का 18) **द्वारा यथा संशोधित हरियाणा भू-जोत सीमा अधिनियम** ***(1972 का 26)*** **- धारा** ***18 (7), (8)*** **और** ***(9)*** **-** ***क्या असंवैधानिक - कानून द्वारा प्रदत्त अपील का अधिकार - क्या इसके प्रयोग के लिए शर्तें लगाकर प्रतिबंधित किया जा सकता है - कुछ मामलों में शर्तों में ढील देने के लिए प्राधिकरण में विवेकाधिकार निहित करने में विफलता- क्या शर्तों को अनुचित बनाता है।***

निर्धारित किया **कि अपील का अधिकार एक गारंटीकृत या संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नागरिकों को दूर-दूर तक इस तरह का कोई अधिकार प्रदान कर सके। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि मूल मंच से अपील करने का कोई अंतर्निहित दावा या अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट है कि सृष्टिकर्ता जो ऐसे अधिकार प्रदान करता है, अर्थात्, विधायिका, समान रूप से उन्हें छीन सकता है। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि यदि इस प्रकार पूरे अधिकार को छीन लिया जा सकता है तो इसे समान रूप से बिगड़ा हुआ, विनियमित या कठिन या अन्यथा स्थितियों के साथ बोझ डाला जा सकता है। इस प्रकार विधायिका पूरी तरह से अपने अभ्यास पर शर्तें या प्रतिबंध लगाकर अपने द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार को विनियमित करने के अपने अधिकार के भीतर है। इसलिए, हरियाणा विधानमंडल ने किसी भी तरह से हरियाणा भूमि होल्डिंग ्स अधिनियम, 1972 की धारा 18 के उप-खंड (7), (8) और (9) को जोड़कर अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है।**

(पैरा 7 and 9).

निर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (7) की भाषा स्पष्ट है और विधायिका की मंशा इस आशय से प्रकट होती है कि जमानत के रूप में जो जमा करने की आवश्यकता है, वह वार्षिक भूमि होल्डिंग्स कर का तीस गुना है। संबंधित प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि वाषक लेवी से अधिक राशि जमा करने की आवश्यकता है। केवल इसलिए कि धारा 12 के तहत भूमि को पहले की तारीख से राज्य में निहित माना जा सकता है, उप-धारा (7) के तहत आवश्यक जमा राशि की मात्रा के संबंध में कम से कम प्रासंगिकता नहीं है। भूमि से वर्तमान कृषि उत्पादन को देखते हुए, हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक एकड़ कृषि भूमि के लिए आवश्यक इस राशि का केवल भुगतान अपील के अधिकार को निरर्थक बना देगा। उप-धारा (8) और (9) के साथ रखी गई योजना में उप-धारा (7) का सही अर्थ लगाते हुए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि अपील के अधिकार के प्रतिबंध और विनियम जो विधायिका ने आवश्यक पाए हैं, वास्तव में बहुत कठिन होने से बहुत दूर हैं। और साथ ही इस भावनात्मक रोने से भी बहुत दूर है कि यह धारा 18 (1) और (2) के तहत दिए गए अपील के सार्थक अधिकार को निरर्थक या भ्रामक बनाता है।

(पैरा 12 और 14)

निर्धारित किया कि कई कारक जिन्होंने विधायिका को प्रेरित किया है और वास्तव में कुछ व्यक्तियों को लगाए गए प्रतिबंधों से छूट देने के लिए किसी भी विवेकाधिकार के

निहित होने से बचने के लिए मजबूर किया है, उन्हें संभवतः भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। उन हजारों अपीलों के संदर्भ में जो अनिवार्य रूप से निर्धारित प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ दायर की जा सकती हैं, अपीलीय न्यायालय के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता की उप-धारा (7) के तहत आवश्यक जमानत जमा करने या न जमा करने की स्थिति और क्षमता की जांच करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। असंख्य भू-धारकों से संबंधित हजारों अपीलों के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा इस तरह की जांच शुरू करने से उस स्तर पर सीलिंग और कृषि कानून की प्रक्रिया में देरी होगी और इस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग के प्रगतिशील उपाय को तेजी से लागू करने के विधायिका के उद्देश्य और इरादे को विफल कर दिया जाएगा। फिर, कलेक्टर द्वारा एक या दूसरे भू-धारकों को एक बार छूट देने की मिसाल का पालन करके अंधाधुंध छूट देना फिर से तुच्छ अपील दायर करने के खिलाफ कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करने के विधायिका के इरादे के उद्देश्य को विफल कर देगा। विधायिका ने ऐसे किसी भी विवेकाधिकार को निहित करने से बचने के लिए आवश्यक पाया था जो मनमाने ढंग से प्रयोग करने में सक्षम हो सकता है और इसलिए, अपीलकर्ताओं में से किसी के मामले में कोई अपवाद नहीं बनाना चाहिए, और उन सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, एक प्रावधान जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान रूप से मानता है, संभवतः नहीं हो सकता है। इसे भेदभावपूर्ण या मनमाना करार दिया जा सकता है। वंचित किए गए बड़े जमींदारों को अधिशेष क्षेत्र के कब्जे में बने रहने का न तो नैतिक अधिकार था और न ही कानूनी अधिकार। फिर भी, पिछले अनुभव से पता चला है कि इस उद्देश्य को कभी-कभी तुच्छ अपील दायर करके हासिल किया गया था और उसके बाद मकान मालिकों द्वारा संशोधन किया गया था, स्पष्ट रूप से अधिशेष क्षेत्र के कब्जे में बने रहने की इच्छा से। यह इस बुराई को कम करने और भूमि के कब्जे में रहने के लिए एक बहाने के रूप में तुच्छ अपीलों और संशोधनों को दायर करने को हतोत्साहित करने के लिए था, जो कानून की नजर में राज्य में निहित था कि विधायिका को अपील और संशोधन के अधिकार को विनियमित करने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। जो कुछ भी किया गया है वह यह है कि इन सभी अपीलों और संशोधनों पर विचार करने के लिए अपीलकर्ता को याचिकाकर्ता को अपने दावे की वास्तविकता के प्रमाण में कुछ सुरक्षा प्रदान करने की शर्त दी गई है।

(पैरा 17 और 18)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 *के तहत प्रार्थना करते हुए याचिका*: –

1. *मामले के संबंधित रिकॉर्ड तलब किए जाएं।*
2. *कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 100 को निर्देश देने की कृपा करे।*
   2. *भूमि होल्डिंग टैक्स का* 30 *गुना जमा करने पर जोर दिए बिना याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करना।*
3. *कि कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे*; जारी किया जाए ;
4. *कि प्रतिवादी को पूर्व नोटिस जारी करने से छूट दी जाए।*
5. *इस याचिका की लागत को याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से *आनंद स्वरूप, आरएस मित्तल, केपी भंडारी, एमएस रत्ता, जीसी नागपाल, वकील।*

उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा के *वरिष्ठ डी.ए.जी. नौबत सिंह के साथ एस.सी. मोहंता,*

ए.जी.

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. पांच सौ चौंतीस संबंधित सिविल रिट याचिकाओं के इस सेट में, जो निर्णय के लिए आता है, वह वास्तव में एक ही बिंदु है, चाहे हरियाणा भूमि होल्डिंग पर सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 18 (7), (8) और (9) के प्रावधान, जैसा कि हरियाणा सीलिंग ओएच लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, 1978 असंवैधानिकता के विकार से पीड़ित है?

2. जैसा कि स्पष्ट है, यहां मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है और वास्तव में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने किसी भी मामले के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया। इसलिए 1977 की मुख्य सिविल रिट याचिका संख्या 3365 का एक पारित संदर्भ इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। इसमें तीन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे 41 कनाई 14 मरला की कृषि भूमि के मालिक हैं और मुख्य रूप से उक्त क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने और हरियाणा भूमि होल्डिंग ्स अधिनियम, 1972 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 12 के तहत राज्य में निहित होने से व्यथित हैं। नतीजतन याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 3, कलेक्टर (निर्धारित प्राधिकरण) के समक्ष अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें घोषणा की राहत मांगी गई कि विवाद में भूमि राज्य में निहित नहीं है और इसलिए, इसका उपयोग अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। इस आवेदन को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 16 मई, 1977 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 2, आयुक्त अंबाला डिवीजन के समक्ष अपील की, जो धारा 18 (2) के आधार पर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी हैं। याचिकाकर्ता मुख्य रूप से धारा 18 (7) के प्रावधानों से व्यथित हैं, जिसमें अपील दायर करने के समय उन्हें विवाद अधिशेष क्षेत्र के संबंध में देय भूमि होल्डिंग टैक्स के तीस गुना के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि उनकी अपील पर विचार किया जाए। यह कहा गया है कि उस आधार पर गणना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को लगभग 1200 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना होगा। संक्षेप में, अधिनियम की धारा 18 द्वारा प्रदत्त अपील और संशोधन के अधिकार पर इस कथित प्रतिबंध को अनुच्छेद 19 (एल) (एफ) के तहत संपत्ति रखने के अधिकार के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है और कई अन्य आधारों पर जिसका संदर्भ अनिवार्य रूप से अनुसरण करेगा।

3. तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है और वास्तव में 25 जुलाई, 1978 को प्रस्ताव की सुनवाई के चरण में, हरियाणा के महाधिवक्ता ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है, प्रतिवादी-राज्य की ओर से कोई रिटर्न आवश्यक नहीं था और परिणामस्वरूप इसे दायर नहीं किया गया था। तथापि, जहां तक कानूनी मुद्दे का संबंध है, चुनौती के अधीन उपबंधों के विधायी इतिहास का संदर्भ आवश्यक और अपरिहार्य दोनों है और इसलिए इसे प्रारंभ में ही किया जा सकता है। हरियाणा राज्य में पूर्ववर्ती भूमि हदबंदी कानून मुख्य रूप से पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 और पेप्सू किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 में निहित था जैसा कि उक्त राज्य पर लागू होता है। हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 को हरियाणा राज्य में भूमि जोतों की अधिकतम सीमा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त

करने के बाद यह 23 दिसंबर, 1972 को लागू हुआ। इसकी धारा 1 में भूमि जोतों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा राज्य के भीतर किसी भी क्षमता में भूमि रखने का हकदार नहीं होगा , जो नियत दिन में मेरे अनुमेय क्षेत्र से अधिक हो या उसमें परिवर्तन न करे। अधिनियम की धारा 8, 9, 10 और 11 निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण और घोषणा की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जबकि धारा 12 ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि भू-स्वामी का अधिशेष क्षेत्र उस तारीख से राज्य सरकार में निहित होगा जिस तारीख को इसे किसी भी दायित्व से मुक्त घोषित किया गया है।

4. धारा 18 की उपधारा 1 और (2) के *तहत* सामग्री प्रावधानों में निर्धारित प्राधिकारी के आदेशों के तहत अपील, समीक्षा और संशोधन का प्रावधान था और मूल रूप से अधिनियमित के अनुसार अपीलीय और संविधि द्वारा पुनरीक्षण उपाय पर कोई पत्र नहीं रखा गया था। तथापि, हरियाणा भू-जोत सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (अधिनियम हो. 40 ओआई 1976) के अधिनियमन द्वारा, अन्य परिवर्तनों के अलावा, धारा 18 की उप-धारा (5) को हटा दिया गया था और उसमें उपधारा (7) और (8) जोड़ी गई थी। धारा 18 की नई सम्मिलित उपधारा (7) में पहली बार यह शर्त लगाई गई है कि उप-धारा (1) या (2) के तहत सभी अपीलों या संशोधनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब विवादित अधिशेष क्षेत्र के संबंध में देय भूमि होल्डिंग कर के तीस गुना के बराबर राशि जमा की जाएगी।

5. अपील और संशोधन के अधिकार के उपर्युक्त विनियमन को सिविल रिट याचिका सं 2008 में चुनौती का विषय बनाया गया था।वर्ष 1977 की रिट याचिका संख्या 3365 को 27 अक्तूबर, 1977 को वरीयता दी गई और इसी प्रकार की कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं। बयालीसवें संशोधन अधिनियम के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह रिट याचिका पहले इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई और प्रारंभिक सुनवाई के बाद हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने यह रुख अपनाया कि प्रतिवादी-राज्य धारा 18 (7) और 18 (8) में संशोधन पर विचार कर रहा था। उपरोक्त रिट याचिका और अन्य संबंधित मामलों को इसलिए आवश्यक संशोधन की प्रतीक्षा करने के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था - बयालीसवें संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के निरसन के परिणामस्वरूप मामला वापस एक खंडपीठ को वापस भेज दिया गया। 6 जून, 1978 को हरियाणा भूमि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1878 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत धारा 18 (7) में परिणामी परिवर्तन किए गए और उप-धारा (8) को उसके मूल रूप में बनाए रखते हुए उसके बाद एक नई उपधारा (9) जोड़ी गई। धारा 18 विद्वान परामर्शदाता में पेश किए गए उपरोक्त परिवर्तनों के बावजूद याचिकाकर्ताओं ने इसकी संवैधानिकता पर अपना हमला किया और प्रश्न के महत्व को देखते हुए, रिट याचिकाओं को एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया।

6. अपरिहार्य यह है कि यहां विवाद धारा 18 के प्रासंगिक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमना है, जिसमें पेश किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में। हालांकि, यह याद रखना पर्याप्त है कि मूल रूप से अधिनियमित धारा 18 ने अपील, समीक्षा और संशोधन का एक अप्रतिबंधित और असीमित अधिकार प्रदान किया था, जो आगे किसी भी शर्त द्वारा विनियमित नहीं था। हालांकि, 1976 के अधिनियम 40 ने उप-धाराओं (7) और (8) को सम्मिलित करके जमा करने की शर्त लगाई, जबकि 1978 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 *के तहत* हाल ही में किए गए संशोधन ने लगाई गई शर्तों की

कठोरता को काफी हद तक कम कर दिया है- हालांकि, विवाद को सही परिप्रेक्ष्य मे समझने के लिए, अधिनियम की धारा 18 में मूल और संशोधित प्रासंगिक प्रावधानों शामिल करना आवश्यक है: —

(9) ……………………………..

यदि अपील या संशोधन सफल होता है, तो जमा की गई राशि या उप-धारा (7) के तहत

*मूल अधिनियम (*1976 *का* अधिनियम 40)	*संशोधित अधिनियम (अधिनियम स 2008)*1978 *का* 18)
18 (1) ***अपील, समीक्षा और संशोधन।-*** **कोई भी व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी के किसी निर्णय या आदेशों से व्यथित है, जो कलेक्टर नहीं है, आदेश के निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कलेक्टर के पास ऐसे रूप और रीति में अपील कर सकता है जो विहित किया जाए;**	***अपील, समीक्षा और संशोधन-*** **कोई भी व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी के किसी निर्णय या आदेशों से व्यथित है, जो कलेक्टर नहीं है, आदेशों के निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कलेक्टर के समक्ष ऐसे रूप और रीति में अपील कर सकता है जो विहित किया जा सकता है;**
परन्तु कलेक्टर पंद्रह दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।	**परन्तु कलेक्टर पंद्रह दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।**
(7) उपधारा (1) और (2) के तहत कोई अपील या उप-धारा (4) के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास विवादित अधिशेष क्षेत्र के संबंध में देय भूमि धारण कर के तीस गुना के बराबर राशि जमा नहीं करता है।	- उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत कोई अपील या उप-धारा (4) के तहत संशोधन नहीं होगा जब तक कि अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, ने विवादित अधिशेष क्षेत्र के संबंध में देय भूमि होल्डिंग्स कर के तीस गुना के बराबर राशि जमा की है या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण के साथ सुरक्षा के रूप में समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।
(8) धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक व्यक्ति जो अपनी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित करने के आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन दायर करता है और उसके द्वारा दायर अपील या संशोधन विफल हो जाता है, उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह अधिशेष घोषित भूमि के कब्जे में है या किसी भी समय रहा है, जिसके लिए वह कानून के तहत हकदार है या नहीं था, भूमि होल्डिंग टैक्स के तीस गुना के बराबर लाइसेंस शुल्क, इस क्षेत्र के संबंध में वसूली योग्य।	**धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक व्यक्ति जो अपनी भूमि को अधिशेष क्षेत्र घोषित करने के आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन दायर करता है और उसके द्वारा दायर अपील या संशोधन विफल हो जाता है, उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह अधिशेष घोषित भूमि के कब्जे में है या किसी भी समय रहा है, जिसके लिए वह कानून के तहत हकदार है या नहीं था, भूमि होल्डिंग टैक्स के तीस गुना के बराबर लाइसेंस शुल्क, इस क्षेत्र के संबंध में वसूली योग्य।**

प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापस कर दिया

जाएगा या जारी किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। यदि अपील या संशोधन विफल हो जाता है, तो नकद में जमा की गई राशि या प्रस्तुत बैंक गारंटी की राशि को उपधारा (8) के तहत वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा।

अब उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान वकील द्वारा काफी दृढ़ता और वाक्पटुता के साथ दिए गए तर्क का मूल यही है। मूल रूप से 1972 में अधिनियमित धारा 18 (1) ने उन्हें निर्धारित या अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील और संशोधन का अप्रतिबंधित और बिना शर्त अधिकार दिया। उस अधिकार को एक निहित अधिकार होने का दावा किया जाता है जिसे विद्वान वकील के अनुसार छीना या छीना नहीं जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि 1976 के अधिनियम 40 में उप-धारा (7) और (8) को जोड़कर अपील के उनके अप्रतिबंधित अधिकार पर रोक लगा दी गई थी, जिसे करने के लिए विधायिका अनधिकृत थी। यहां तक कि हरियाणा भूमि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1978 के *तहत* हाल ही में संशोधन द्वारा उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने से भी वकील के अनुसार किसी भी तरह से असंवैधानिकता की बुराई को दूर नहीं किया गया है। एक चरम पर, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं को हर प्रतिबंध या बाद के कानून द्वारा उस पर रोक लगाने के लिए अपील का निहित अधिकार अनुचित था। यदि तब ऐसा था, तो इसे थोड़ा कम करने का तर्क यह दिया गया था कि संशोधित उप-धाराएं (7) और! ('8') और धारा 18 की नई जोड़ी गई उपधारा (9) प्रकृति में इतनी कठिन थी कि उन्होंने या तो अपील के निहित अधिकार को छीन लिया या किसी भी मामले में इसे भ्रामक बना दिया।

7. पूर्वोक्त प्रस्ताव को जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया गया और दबाया गया, उसके बावजूद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील के अधिकार की प्रकृति और सामग्री के संबंध में एक बुनियादी भ्रम से उपजा है, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अपील का अधिकार एक गारंटीकृत या संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नागरिकों को दूर-दूर तक इस तरह का कोई अधिकार प्रदान करता हो। वास्तव में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि अपील का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और न ही संवैधानिक है। ऐसा होने पर, यह समान रूप से स्पष्ट है कि मूल मंच से अपील करने का कोई अंतर्निहित दावा या अधिकार नहीं है। इसलिए, बार-बार यह कहा गया है कि अपील का अधिकार केवल क़ानून का एक प्राणी है। यदि ऐसा है, तो यह स्पष्ट है कि निर्माता जो ऐसे अधिकार प्रदान करता है, अर्थात् विधायिका समान रूप से उन्हें दूर कर सकती है। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि यदि पूरे अधिकार को वह इस प्रकार छीन सकता है तो इसे समान रूप से बिगड़ा हुआ, विनियमित या कठिन या अन्यथा स्थितियों के साथ बोझ डाला जा सकता है।

8. ऐसा लगता है कि कानूनी स्थिति इतनी स्पष्ट है और बाध्यकारी मिसाल द्वारा समर्थित है करना सिद्धांत पर एक लंबा शोध प्रबंध स्पष्ट रूप से बेकार होगा। *मेसर्स गोरधन दस्त बलदेव दास* बनाम गवर्नर जनरल[1] *इस न्यायालय की पूर्ण पीठकाउंसिल* में, जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्वयं इस प्रस्ताव पर भरोसा किया था कि अपील का अधिकार केवल एक प्रक्रियात्मक अधिकार नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अधिकार है, ने

[1] एआईआर 1952 पीबी 103

बिना किसी अनिश्चित शब्दों में निम्नानुसार माना है: -

> **«* * *. यद्यपि जैसा कि हम समझते हैं कि कानून यह आवश्यक मानता है कि एक वादी, जो एक न्यायालय के आदेश से व्यथित है, को अपने मामले की जांच एक उच्च न्यायाधिकरण द्वारा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह कुछ हद तक विरोधाभास है कि निचली अदालत ने तथ्य या कानून के दृष्टिकोण से गलत निर्णय दिया है, इंग्लैंड के सामान्य कानून के लिए पूरी तरह से अज्ञात था। अपील का अधिकार एक प्राकृतिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है जो प्रत्येक वादी को एक मामले या पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध है; यह केवल एक विधायी विशेषाधिकार है जिसे कानून बनाने वाला प्राधिकारी प्रदान कर सकता है या पुराना कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानमंडल के पास अपील का अधिकार प्रदान करने या छीनने और यह निर्धारित करने की पूर्ण शक्तियां हैं कि किन मामलों में, किन परिस्थितियों में, किस रीति से और किन न्यायालयों से अपील की जाए। यही कारण है कि अपीलों को आमतौर पर क़ानून के प्राणियों के रूप में माना जाता है"।**

(9) इस संदर्भ में यह मामला चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) द्वारा श्रीमती गंगा बाई बनाम *विजय कुमार और अन्य,*[2] में वाद के अधिकार और अपील के अधिकार के बीच बुनियादी अंतर को उजागर करने से समाप्त होता प्रतीत होता है: –

> **"* * *. इस सवाल पर स्थिति हमें अच्छी तरह से स्थापित लगती है। मुकदमे के अधिकार और अपील के अधिकार के बीच एक बुनियादी अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति में सिविल प्रकृति का मुकदमा लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है और जब तक मुकदमे को क़ानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी अपनी पसंद का मुकदमा ला सकता है, यह मुकदमे का कोई जवाब नहीं है, चाहे वह दावा कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कि कानून मुकदमा करने का ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। एक मुकदमे को बनाए रखने के लिए कानून के किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून मुकदमे को रोकता नहीं है। लेकिन अपील ों के संबंध में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अपील का अधिकार किसी में नहीं है और इसलिए, इसकी विचारणीयता के लिए अपील को कानून का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। यह बताता है कि अपील के अधिकार को क़ानून के प्राणी के रूप में क्यों वर्णित किया गया है।**

एक बार जब यह आयोजित किया जाता है, जैसा कि यह आवश्यक होना चाहिए कि अपील का अधिकार केवल विधायिका द्वारा प्रदान किए जाने से उपजा है, तो यह समान रूप से स्पष्ट है कि वही प्राधिकरण कठिन परिस्थितियों के साथ इसे विनियमित, बाधित या हेज कर सकता है। यह स्थिति, सिद्धांत पर स्पष्ट होने के अलावा, बाध्यकारी मिसाल द्वारा समान रूप से कवर की जाती है। *बॉम्बे राज्य* बनाम मैसर्स *सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड,*[3] में न्यायमूर्ति एस. के. दास ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस बिंदु पर कई अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> **"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित निर्णयों की एक लंबी पंक्ति में और कम से कम इस न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले में, यह माना गया है कि उस पर एक नया प्रतिबंध लगाकर या अधिक कठिन शर्त लगाकर अपील के अधिकार का उल्लंघन केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है;**

[2] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1126
[3] ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 980

यह एक मौलिक अधिकार को बाधित करता है या खतरे में डालता है और ऐसा करने वाला एक अधिनियमन पूर्वव्यापी नहीं है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से ऐसा न कहे।

उपरोक्त टिप्पणियां स्पष्ट रूप से इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ सकती हैं कि न केवल विधायिका अपील के अधिकारों को खराब करने, खतरे में डालने या कठोर शर्तों के साथ प्रतिबंधित करने की हकदार है, बल्कि यह पूर्वव्यापी रूप से या तो एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक इरादे से ऐसा करके आगे बढ़ सकती है। मेरे विचार से यह मामला अनंत मिल्स बनाम *गुजरात राज्य*[4], मुंहनाथ मामले में खन्ना, जे की वजनदार टिप्पणियों से समाप्त होता है । जिसे याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था। अपीलीय प्रावधान के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत हमले को रोकना जिसमें अपील के मनोरंजन से पहले कर जमा करना आवश्यक था, यह देखा गया था: ->

"अपील का अधिकार एक क़ानून का प्राणी है। इस तरह के अधिकार बनाने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना, पीड़ित व्यक्ति अपील दायर करने का हकदार नहीं है। हम यह समझने में विफल हैं कि अपील का अधिकार देते समय विधायिका इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें क्यों नहीं लगा सकती है। किसी विशेष कारण के अभाव में ऐसी शर्तों को लागू करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आपराधिक मामलों में यह शर्त निर्धारित करने की अनुमति है कि जब तक किसी दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तब तक उसे कारावास की सजा के खिलाफ उसकी अपील पर विचार करने से पहले हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा: इसी तरह, एक कानून बनाने की अनुमति है कि कर के आकलन से संबंधित आदेश के खिलाफ कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि कर का भुगतान नहीं किया गया हो। ऐसा प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 30 में कानून की किताब में था। उस धारा के परंतुक में यह प्रावधान किया गया था कि धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि कर का भुगतान नहीं किया गया हो- ऐसी शर्तें केवल अपील के अधिकार के प्रयोग को विनियमित करती हैं ताकि उद्दंड पक्ष द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जाए और अपील के अंततः खारिज होने की स्थिति में अपील के खिलाफ अपील के प्रवर्तन में कोई कठिनाई न हो। यह विधायिका के लिए खुला है कि वह किसी ऐसे पक्ष पर एक साथ दायित्व लागू करे जिस पर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है या अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें निर्धारित करे। यदि संबंधित पक्ष उक्त अधिकार का लाभ उठाना चाहता है तो उस दायित्व के निर्वहन या उस शर्त को पूरा करने की कोई भी आवश्यकता कानून का एक वैध टुकड़ा है, और हम इसमें अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं देख सकते हैं।

इसलिए, इस पहलू पर, यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि विधायिका अपने अभ्यास पर शर्तें या प्रतिबंध लगाकर अपने द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार को विनियमित करने के अपने अधिकार के भीतर पूरी तरह से है। इसलिए, हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 18 में उप-खंड (7), (8) और (9) को जोड़कर

[4] ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1234

किसी भी तरह से अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है।

(10) अब मुख्य तर्क का दूसरा लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा इस आशय का है कि धारा 18 की उप-धारा (7) द्वारा अपील के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में इतने कठिन हैं कि अपील के अधिकार को वस्तुतः निरर्थक बना देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि उप-धारा (7) एक हाथ से वह सब कुछ छीन लेती है जो पहले की उप-धारा (1) ने दूसरे हाथ से दी थी। इस तर्क को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया था कि उप-धारा (7) की विषय-वस्तु इतनी अस्पष्ट थी कि इसमें भूमि धारण कर की मात्रा को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जो अपीलकर्ता द्वारा यूआईई पर देय था, जिसके लिए इसे जमा किया जाना था, धारा 12 के ऑनलाइन संशोधित प्रावधानों के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि अधिशेष भूमि राज्य में निहित है।अपनी मूल घोषणा की तारीख से, यहां तक कि पिछले क़ानून के तहत, इसलिए, एक विशेष अपीलकर्ता ऐसी स्थिति में दस साल या उससे अधिक समय तक की भूमि को जमा करने के लिए मजबूर हो सकता है, गलत संदर्भ में यह अंततः प्रस्तुत किया गया था कि बड़े भूमि-धारकों के मामले में जो सैकड़ों भूमि के मालिक हो सकते हैं। ऐसी एकड़ भूमि जिसे अधिशेष घोषित किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों के संबंध में उपर्युक्त भूमि धारण कर का भुगतान करने के लिए बहुत बोझिल हो जाएगी।

(11) मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त विवाद उप-धारा (i) के सादे प्रावधानों की किसी गलत धारणा या गलत व्याख्या से उत्पन्न *होते हैं* और किसी भी मामले में उन स्थितियों की कल्पना करने के लिए एक उपजाऊ कल्पना से उपजी बोगियों को उठाते हैं जो शायद ही उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होने की संभावना भी होती है। यह दलील कि उप-धारा (7) इस आधार पर अस्पष्ट है, कि यह उस मात्रा या अवधि को निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके लिए धन होल्डिंग कर जमा किया जाना है क्योंकि सुरक्षा कानून के सादे पठन पर भी पानी नहीं डाल सकता है। इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि विवादित अधिशेष क्षेत्र के संबंध में देय भूमि जोत कर के तीस गुना के बराबर राशि जमा की जानी है- हरियाणा भूमि होल्डिंग्स कर अधिनियम, 1973 का केवल संदर्भ देने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसकी धारा 5 और अधिनियम के अन्य प्रावधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि भूमि होल्डिंग ्स टैक्स जो भूमि होल्डिंग्स पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समेकित करता है, एक वार्षिक कर है। उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में कर के प्रभाव को वर्गीकृत करने के लिए भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी के प्रकार आदि को बहुत विस्तार से विनिदष्ट किया गया है, जबकि अनुसूची II सावधानीपूर्वक भूमि जोत कर की दरों को सबसे अधिक विस्तार से निर्धारित करती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उप-धारा (7) द्वारा विचार ति जमा राशि स्पष्ट रूप से वार्षिक भूमि होल्डिंग ्स टैक्स पर आधारित है, जो फिर से हरियाणा लैंड होल्डिंग्स टैक्स, अधिनियम 1972 के विस्तृत प्रावधानों द्वारा सटीक रूप से निर्धारित की जाती है। क़ानून की सीधी व्याख्या के अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता ने स्वयं एक निष्पक्ष और दृढ़ रुख अपनाया कि जमा वार्षिक कर से संबंधित था और इसकी मात्रा क़ानून द्वारा ठीक से तय की गई थी। हमारे सामने यह आम मामला था कि उक्त प्रावधान के तहत वार्षिक कर केवल एक एकड़ कृषि भूमि के संबंध में 8 रुपये के मामूली आंकड़े के आसपास था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उप-धारा (7) के संबंध में अस्पष्टता का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है।

(12) एक बार फिर इस तरह का काल्पनिक मुद्दा उठाया जा रहा है कि किसी विशेष मामले में अपीलकर्ता को उपधारा (7) के तहत कई वर्षों के लिए भूमि होल्डिंग कर जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि पहले ही देखा गया है, भाषा सादा है और विधायिका का इरादा इस प्रभाव से प्रकट होता है कि क्या आवश्यक है। जमानत राशि वार्षिक भूमि होल्डिंग्स के कर का तीस गुना है। वहां: संबंधित प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभवतः वार्षिक लेवी से अधिक जमा करने की आवश्यकता का अर्थ लगा सकता है। केवल इसलिए कि

धारा 12 के तहत भूमि को निहित माना जा सकता है। राज्य में पहले की तारीख से इसकी मात्रा के संबंध में कम से कम प्रासंगिकता नहीं है। उप-धारा (7) के तहत आवश्यक जमा राशि का विवरण। एक बार ऐसा ही होता है, यह। यह स्पष्ट है कि लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1976 के संदर्भ में जब राशि निर्धारित की जाती है, तो यह कुल मिलाकर लगभग 240 रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो जाती है। को देखते हुए। हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में भूमि से कृषि उत्पादन को वर्तमान में यह वास्तव में एक साहसी व्यक्ति होगा जो कह सकता है कि एक एकड़ कृषि भूमि के लिए आवश्यक इस राशि का केवल भुगतान अपील के अधिकार को निरर्थक बना देगा। याचिकाकर्ता स्वयं जमा राशि की मात्रा के निहितार्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं, यह रिट याचिका के पैराग्राफ 7 के समापन भाग में दिए गए कथनों से स्पष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें 1,200 रुपये की राशि जमा करनी होगी। लगभग पांच एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए। तक। दोहराएं, यह शायद ही कभी कहा जा सकता है' कि 'तुच्छ अपीलों को दायर करने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में जमा राशि की उपरोक्त मात्रा और ज्यादातर मामलों में उसके लंबित रहने के दौरान भूमि को बनाए रखना या तो अनुचित रूप से कष्टदायक है या प्रकृति का है कि अपील के अधिकार को ही नष्ट कर देता है।

(13) फिर भी इस तर्क के खिलाफ कि उप-धारा (7) के तहत एक विशेष अपीलकर्ता को सैकड़ों एकड़ या उससे अधिक के संबंध में वार्षिक भूमि होल्डिंग कर जमा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, हरियाणा राज्य के भीतर और शायद पूरे देश में कृषि कानून के पूर्ववर्ती इतिहास से आंखें मूंदता प्रतीत होता है। होल्डिंग्स में पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम शामिल था जो हरियाणा राज्य पर लागू होता है। इसमें अनुमेय क्षेत्र, दोनों भूमि। मालिकों और किरायेदारों ने किसी भी मामले में तीस मानक एकड़ से अधिक नहीं किया। यह भी याद रखना होगा कि 1949 के बाद से लगभग तीस वर्षों की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा में अधिकतम सीमा और कृषि कानून उत्तरोत्तर लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में अब सैकड़ों या हजारों एकड़ भूमि की कल्पना करने के अलावा कुछ भी नहीं है, अपील के अधिकार की भ्रामक प्रकृति का आरोप लगाने वाले तर्क को खारिज करते हुए, मैं उप-धारा (7) को उस योजना में सही ढंग से समझने के लिए इच्छुक हूं जिसमें इसे उप-धारा (8) और (9) के साथ रखा गया है। इस निष्कर्ष से कोई बच ता नहीं दिख रहा है कि अपील के अधिकार पर प्रतिबंध और विनियमन, जिसे विधायिका ने आवश्यक पाया है, वास्तव में या तो बहुत कष्टदायक है और समान रूप से भावनात्मक रोना से बहुत दूर है कि यह धारा 18 (1) और (2) के तहत दिए गए अपील के सार्थक अधिकार को प्रस्तुत करता है।

(14) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तब धारा 18 की प्रतिबंधात्मक उप-धाराओं (7), (8) और (9) को इस आधार पर खारिज करने का प्रयास किया था कि विधायिका ने किसी भी प्राधिकरण में इसमें ढील देने या अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत मामले में छूट देने का कोई विवेक निहित नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आधे-अधूरे मन से तर्क दिया गया था कि उन सभी कानूनों में जो अपील के अधिकार को कम करने के लिए एक प्राधिकारी में निहित विवेकाधिकार के बिना अपील के अधिकार को समाप्त करते हैं, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि दंड असंवैधानिक है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(16) मुझे इस विवाद में भी ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं की आकाशगंगा, दबाव डालने के बावजूद, इस प्रस्ताव के समर्थन में कोई अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकी कि जब तक छूट देने का विवेकाधिकार किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है, अपील या संशोधन के अधिकार पर हर प्रतिबंध अनुचित है। वास्तव में, जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में पहले ही देखा जा चुका है, मिसाल पूरी तरह से विपरीत है, न ही विद्वान वकील उपरोक्त विवाद के

समर्थन में किसी ठोस सिद्धांत का हवाला दे सकते हैं।

(17) हरियाणा के एडवोकेट-जनरल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपरोक्त तर्क को पूरा करते हुए स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि अपील के अधिकार के विनियमन को केवल अपीलकर्ताओं या याचिकाकर्ताओं को लगाए गए प्रतिबंधों से छूट देने के लिए विवेकाधिकार के अभाव के एकमात्र आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। वकील ने विशेष रूप से भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 30 पर प्रकाश डाला, जिसमें अपील पर विचार करने से पहले कर जमा करना आवश्यक था और जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले चालीस साल तक इस क्षेत्र में रहा था। अनंत मिल्स में इस विशेष संदर्भ में रिलायंस को उनके लॉर्डशिप की टिप्पणियों पर भी सही रखा गया *थी?* केस (सुप्रा)। इसके अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता श्री चंद आदि हैं। *(v)* हरियाणा राज्य आदि (एस. एस. संधावालिया, सी.जे.) उन्होंने कई कारकों की ओर इशारा किया, जिन्होंने विधायिका को कलेक्टर के स्तर पर ऐसी किसी भी शक्ति को निहित करने से बचने के लिए प्रेरित किया और वास्तव में मजबूर किया, जो ज्यादातर मामलों में निर्धारित प्राधिकारी के निर्णय से अपीलीय मंच हो सकता है । **उन्होंने बताया कि हजारों या यहां तक कि दसियों हजार अपीलों के संदर्भ में, जो अनिवार्य रूप से निर्धारित प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर की जा सकती हैं, अपीलीय न्यायालय के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता की स्थिति और क्षमता की जांच करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, उप-धारा (7) के तहत आवश्यक जमानत जमा करने या जमा करने के लिए नहीं। विद्वान वकील इस बात पर दृढ़ थे कि असंख्य भू-स्वामियों से संबंधित हजारों अपीलों के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा इस तरह की जांच शुरू करने से उस स्तर पर सीलिंग और कृषि कानून की प्रक्रिया में देरी होगी और सोशल इंजीनियरिंग के प्रगतिशील उपाय के रूप में प्रतीत होने वाले विधायिका के उद्देश्य और इरादे को तेजी से लागू करने में देरी होगी। आगे यह तर्क दिया गया कि ऐसी स्थिति में एक कलेक्टर द्वारा एक या अन्य भूमि-धारकों को छूट देने को उनके पक्ष में एक अपमानजनक भेद या अनावश्यक विवेक के रूप में माना जा सकता है- श्री मोहनता ने यहां तक तर्क दिया कि कलेक्टर, हालांकि अधिनियम के तहत अर्ध-न्यायिक कार्यों का उपयोग करते हैं, फिर भी मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी हैं और उन्हें इस तरह के विवेक के साथ निहित करने से दबाव के कारण अनावश्यक रूप से इसे खतरे में पड़ सकता है। विभिन्न स्रोतों से कुछ पसंदीदा लोगों के पक्ष में उक्त विवेक ाधिकार का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरों के मामले में इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। आगे यह बताया गया कि कलेक्टर द्वारा एक या दूसरे भूमि-धारकों को एक बार छूट देने की परंपरा का पालन करके अंधाधुंध छूट देना फिर से तुच्छ अपील दायर करने के खिलाफ कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करने के विधायिका के उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा। इसलिए, यह बताया गया कि विधायिका ने इस तरह के किसी भी विवेकाधिकार को निहित करने से बचने के लिए यह आवश्यक बना दिया था कि मनमाने ढंग से प्रयोग करने में सक्षम हो सकता है और इसलिए, इन कार्यवाहियों में अपीलकर्ताओं या याचिकाकर्ताओं में से किसी के मामले में कोई अपवाद नहीं बनाया जाए और उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसलिए, यह बलपूर्वक और सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि एक प्रावधान जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान रूप से मानता है, उसे संभवतः भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है और ऊपर वर्णित तथ्यों के अजीब संदर्भ में और भी अधिक।**

(18) **वास्तव में जब इस मामले को कृषि और अधिकतम सीमा कानून के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में देखा जाता है, तो हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता यह तर्क देने में बहुत दृढ़ आधार पर प्रतीत होते हैं कि उप-धाराओं (7), (8) और (9) के मध्यम**

प्रावधानों द्वारा अपील के अधिकार का विनियमन न केवल उचित था, बल्कि वास्तव में बिल्कुल आवश्यक था यदि राज्य के भीतर भूमि जोत ोें की सीमा को कोई अर्थ या सामग्री दी जानी थी। वकील ने हमारा ध्यान बड़े भू-धारकों की प्राकृतिक इच्छा और अपरिहार्य प्रयासों की ओर आकर्षित किया, जो अधिशेष क्षेत्र से चिपके रहने के लिए थे, जहां से उन्हें अलग कर दिया गया था और कुछ मामलों में सभी प्रगतिशील कानूनों के वास्तविक कार्यान्वयन को विफल करने के लिए। यह कभी-कभी व्यक्तिगत मामलों में सफलता की डिग्री के साथ किया गया है और यहां तक कि सामूहिक रूप से भी शायद इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह ठीक ही बताया गया था कि पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम और पेप्सू किरायेदारी अधिनियम के साथ-साथ हरियाणा भूमि होल्डिंग ्स अधिनियम की धारा 12 के पूर्व प्रावधानों के आधार पर, इस प्रकार घोषित अधिशेष क्षेत्र भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन द्वारा उपयोग के उद्देश्य के लिए स्वचालित रूप से राज्य में निहित है। ऐसा होने पर, विद्वान एडवोकेट-जनरल बलपूर्वक यह तर्क देने में सक्षम थे कि बड़े जमींदारों को अधिशेष क्षेत्र के कब्जे में बने रहने का न तो नैतिक और न ही कानूनी अधिकार था। फिर भी पिछले अनुभव से पता चला है कि, इस उद्देश्य को कुछ समय के लिए तुच्छ अपील दायर करने और उसके बाद संशोधन करने में हासिल किया गया था (जमींदारों ने स्पष्ट रूप से अधिशेष क्षेत्र के कब्जे में बने रहने की इच्छा से लुभाया था)। यह इस बुराई को कम करने और भूमि के कब्जे में बने रहने के लिए तुच्छ अपीलों और संशोधनों को दायर करने को हतोत्साहित करने के लिए था, जो कानून की नजर में राज्य में निहित था कि विधायिका को अपील और संशोधन के अधिकार को विनियमित करने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। जो कुछ भी किया गया है वह यह है कि इन सभी अपीलों और संशोधनों पर विचार करने के लिए अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता को अपने दावे की वास्तविकता के प्रमाण में कुछ सुरक्षा प्रस्तुत करने की शर्त दी गई है - कानून के सादे प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था जिसने विधायिका के इरादे को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसे "उद्देश्यों और कारणों के बयान द्वारा अधिक स्पष्ट किया गया है। विधेयक, जो 1976 के अधिनियम संख्या 40 के अधिनियमन में समाप्त हुआ। हरियाणा सरकार के दिनांक 2 जुलाई, 1976 के राजपत्र में प्रकाशित इन पर स्पष्ट नोटिस दिया जाना चाहिए-

उन्होंने कहा, "मार्च में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप। 1976. भारत सरकार ने अन्य *बातों के साथ-साथ* यह सुझाव दिया कि हरियाणा भू-जोत सीमा अधिनियम, 1972 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अपील और संशोधन की अवधि को कम किया जा सके, जमा राशि के भुगतान को निर्धारित करके तुच्छ आधार पर अपील की संस्थाओं को हतोत्साहित किया जा सके, वकीलों की उपस्थिति पर रोक लगाई जा सके, और यह भी प्रावधान किया जा सके कि उन भूस्वामियों की अधिशेष भूमि के एक हिस्से के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए जो घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। गलत सूचना वाली घोषणाएं प्रस्तुत करें और भूस्वामियों को उनकी अपील/संशोधन की विफलता की स्थिति में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

उपर्युक्त सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया था और अधिनियम की धारा 12 और धारा 15 में संशोधन के साथ उपर्युक्त संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। बाद वाले खंड में संशोधन किया जाना है ताकि किरायेदारों की कुछ विनिदष्ट श्रेणियों को अधिशेष भूमि के आवंटन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके और अधिशेष भूमि के आवंटन के माप को भी कम किया जा सके ताकि आवंटन की योजना का लाभ अधिकतम पात्र व्यक्तियों को दिया जा सके। तदनुसार, 5 मई, 1976 को हरियाणा भूमि जोत

सीमा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 को प्रख्यापित किया गया था, क्योंकि उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था। अब उक्त अध्यादेश को वर्तमान कानून के साथ बदलने का प्रस्ताव है।

इसलिए, विधायिका का प्रकट और दोहरा इरादा, भूमि के कब्जे को बनाए रखने के लिए तुच्छ अपीलों और संशोधनों को रोकना और उस पर अनधिकृत कब्जे के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में कुछ सुरक्षा प्राप्त करने में उनकी विफलता की स्थिति में, धारा 18 की उप-धाराओं (7) और (8) में उल्लिखित किया गया था, जिन्हें उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। महाधिवक्ता आगे यह बताने में सक्षम थे कि अधिशेष कृषि भूमि के कब्जे में बने रहने और जारी रखने के बहुत मूल्यवान अधिकार के लिए अधिकांश मामलों में, अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं को कोई अदालत-शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है और यहां अपील के अधिकार के विनियमन के लिए मुख्य रूप से प्रतिभूति की प्रकृति में भूमि होल्डिंग कर का तीस गुना जमा करने की आवश्यकता होती है। तुच्छ अपीलें और उनकी विफलता। यह उप-धाराओं (7) और (8) के मूल सम्मिलन के चरण में था और वकील ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हाल के संशोधन द्वारा वास्तव में अपील के अधिकार के उपरोक्त विनियमन को और उदार बनाया गया है और विषय के पक्ष में कम किया गया है।

(19) तथापि, हाल ही में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भूमि जोत सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18) के प्रावधानों, उद्देश्यों और अधिनियमन के तरीके का विशेष संदर्भ मांगा गया है। यह स्मरण करने योग्य है कि यह संशोधन अधिनियम तत्कालीन मौजूदा उप-धाराओं (7) और (8) को इस न्यायालय में दी गई चुनौती के लिए विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से एक प्रतिक्रिया थी। इस न्यायालय के समक्ष हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने स्वयं निष्पक्ष रूप से यह रुख अपनाया था कि विधायिका स्वयं इस प्रावधान को संशोधित करेगी ताकि इसकी कथित कठोरता को कम किया जा सके और इसे उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप बनाया जा सके। उस आश्वासन के अनुसरण में उप-धारा (7) में संशोधन किया गया था और एक नई उप-धारा (9) जोड़ी गई थी। इस मामले को संदेह से परे रखने के लिए, उद्देश्यों और कारणों के कथन का संदर्भ दिया जा सकता है जो अंततः नए प्रावधान के अधिनियमन में परिणत हुआ। इसके लिए उद्धरण की आवश्यकता होती *है*:-

> "हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 की धारा 18 की मौजूदा उप-धारा (7) में कहा गया है कि अपील/संशोधन दायर करने से पहले, एक भूस्वामी को अपील/पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास विवादित अधिशेष क्षेत्र के संबंध में भूमि होल्डिंग कर के 30 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि, उक्त प्रावधान यह इंगित नहीं करता है कि इसके तहत जमा की जाने वाली राशि अदालत शुल्क है या अपील/संशोधन दायर करने के लिए लिया जाने वाला कोई अन्य शुल्क है, या अपीलकर्ता के सफल होने की स्थिति में उक्त राशि वापस कर दी जाएगी। किसी भी संदेह से परे उक्त प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए, धारा 18 की उप-धारा (7) में संशोधन करने और अधिनियम की धारा 18 में एक नई उप-धारा (9) जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जमा की जाने वाली राशि या उसके तहत प्रस्तुत की जाने वाली समान राशि की बैंक गारंटी को प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा, यदि अपील/संशोधन सफल होता है, तो इसे वापस कर दिया जाएगा या

जारी किया जाएगा, और यदि अपील/संशोधन विफल हो जाता है, तो उक्त राशि को उस राशि के साथ समायोजित किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (8) के तहत देय हो जाएगी।

(20) 1978 के एम्जिंग एक्ट के बाद की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, विद्वान एडवोकेट जनरल। हरियाणा ने सही कहा है कि प्रावधानों को अब पूरी तरह से और काफी हद तक याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बदल दिया गया है। अपील या संशोधन के साथ अपेक्षित जमा राशि मात्र एक प्रतिभूति होने के अलावा, इसके लिए एक विकल्प प्रदान किया गया है जो समान राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया है। व्यवहार्यता के साथ यह तर्क दिया गया था कि भूमि बंधक और सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक सुविधाओं के अस्तित्व में आने के साथ, किसी भी कठोर नकदी को जमा करने के बजाय भूमि और संपत्ति के खिलाफ बैंक गारंटी उपलब्ध थी। वकील ने उपधारा (9) के प्रावधान पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अपील या संशोधन के मामले में पूरी राशि या बैंक गारंटी की वापसी का प्रावधान है, जैसा भी मामला हो। प्रतिवादी राज्य की ओर से विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि बैंक गारंटी की जमा राशि न तो अदालत शुल्क है और न ही इसके साथ अपील या संशोधन दायर किए जाने के बाद पूरी तरह से खो सकती है। यह लाइसेंस शुल्क की एक निर्धारित राशि है जिसे उप-धाराओं (8) और (9) के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से सफल अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाता है और यहां तक कि अपील या संशोधन की विफलता की स्थिति में, केवल यह किया जाना है कि उक्त राशि को भूमि के अनधिकृत उपयोग और कब्जे के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में समायोजित किया जाएगा। तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(21) विद्वान महाधिवक्ता ने तब सही कहा कि जमा राशि उप-धारा के तहत है। (7) अनुमेय क्षेत्र के अतिरिक्त अधिशेष घोषित क्षेत्र के मामले में कहा जाता है। यह स्पष्ट व्यवहार्यता के साथ तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता और याचिकाकर्ता कुल मिलाकर मकान मालिकों का एक वर्ग हैं जिनकी होल्डिंग कानून के तहत प्रदान किए गए अनुमेय क्षेत्र से अधिक है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र अधिशेष की घोषणा से व्यथित व्यक्ति कंगालों का एक वर्ग है जो धन का उचित जमा करने में भी असमर्थ हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील के अधिकार में भूमि के मूल्य से संबंधित कोई अदालत शुल्क शामिल नहीं है (जो कब्जे के लिए एक साधारण मुकदमे के मामले में भी प्राथमिक है), और अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को, इसकी कुल अनुपस्थिति में, अपील की विफलता की स्थिति में लाइसेंस शुल्क के रूप में धन का उचित जमा करना होगा, जिसे शायद ही कठिन कहा जा सकता है। यह सही तर्क दिया गया था कि हरियाणा राज्य के भीतर भूमि-धारकों में प्राप्त भूमि के स्थानिक प्रेम के साथ, यह संभवतः यह नहीं कहा जा सकता है कि) एक भूमि-मालिक द्वारा 240 रुपये प्रति एकड़ की राशि जमा करना, जिसके पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक क्षेत्र है, एक ऐसी शर्त है जो उसके अपील के अधिकार को छीन लेती है।

(22) मेरा विचार है कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में अपील के अधिकार का विनियमन, विशेष रूप से हरियाणा सीमा विधान की पृष्ठभूमि में धारा 18 की उप-धाराओं (7), (8) और (9) के माध्यम से इसके हाल के संशोधन के बाद, न केवल पूरी तरह से मध्यम और उचित है, बल्कि उस कानून के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए शायद आवश्यक है।

(23) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्षता के साथ, कोई भी उनकी कुछ दलीलों का उल्लेख करने के लिए मजबूर महसूस करता है जो उनके सामने पूरी तरह से अस्थिर प्रतीत होते हैं- हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि अनुच्छेद 14 स्थिति की ओर आकर्षित था और इसका उल्लंघन किया गया था क्योंकि धारा 18 की उप-धारा (7) से (9) व्यक्तियों के दो वर्गों के साथ व्यवहार करती थी - अर्थात् वे जो जमा कर

सकते हैं और जो ऐसा करने में असमर्थ हैं। असमान और अनुचित तरीके से। सैद्धांतिक रूप से इस विचित्र विवाद की जांच sary.to की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत मिल्स कंपनी, लिमिटेड आदि में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप की निम्नलिखित टिप्पणियों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला *गया है।*

> **"उस दायित्व के निर्वहन या उस शर्त को पूरा करने के लिए कोई भी आवश्यकता यदि संबंधित पक्ष उक्त अधिकार का लाभ उठाना चाहता है, तो यह कानून का एक वैध टुकड़ा है, और हम इसमें अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं देख सकते हैं। किसी पार्टी की अपनी चूक या चूक से उत्पन्न विकलांगता या नुकसान को संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए अपमानजनक दो वर्गों के निर्माण के समान नहीं माना जा सकता है, खासकर जब वह विकलांगता या नुकसान उन सभी व्यक्तियों पर संचालित होता है जो चूक या चूक करते हैं।**

(24) इसके बाद हम पर बार-बार और लगातार दबाव डाला गया कि हम भूमि हदबंदी कानून की असंवैधानिकता या अन्यथा के आधार पर नए सिरे से आगे बढ़ें, वकील ने तब हौवा खड़ा किया कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 की धारा 2 (ए), 9 (4), 12 और 16 प्रकृति में जब्ती हैं और अनुच्छेद 31 के तहत गारंटीकृत संपत्ति के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस विवाद में नए सिरे से नहीं घसीटा जा सकता है कि *श्रीमती जसवंत कौर और एक अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य*[5] *न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले में* उपर्युक्त उपबंधों को श्रेणीबद्ध रूप में सही ठहराया है। यहां तक कि उस दृष्टिकोण की शुद्धता को भी हमारे सामने गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी। उस निर्णय से बाध्य होने के कारण, हम उन्हीं प्रावधानों की संवैधानिकता पर विचार करने या नए सिरे से विचार करने में असमर्थ हैं। इसी तरह इस संदर्भ में यह याद रखना उचित है कि पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1973 के समान प्रावधानों को सरोज कुमारी आदि बनाम ***हरियाणा राज्य आदि*[6] **में डिवीजन बेंच के फैसले द्वारा बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय की उपरोक्त खंडपीठ ने पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1973 में निर्धारित "परिवार" की परिभाषा को रद्द कर दिया था, जिसे बाद में डीजी में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा उलट दिया गया था। *महाजन आदि,* बनाम *राज्य महाराष्ट्र*[7] में पूरे अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया था।**

(25) मुख्य रूप से हरियाणा सीलिंग कानून की कथित अंतर्निहित असंवैधानिकता और जब्ती प्रकृति के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि अपील का अधिकार, जब यह संपत्ति के इस अधिकार को छूता है, तो यह अपने आप में कमोबेश एक (उक्त संपत्ति को रखने का मौलिक अधिकार) की प्रकृति में बदल जाता है और इसलिए, अपील के अधिकार पर लगाए गए किसी भी अनुचित प्रतिबंध में अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल होगा।

(26) जबकि हम इस स्कोर पर सलाह की सरलता से थोड़ा खुश हैं, यह लगभग प्रकट होता है कि सबमिशन भ्रामक है। ऊपर दर्ज विस्तृत कारणों के लिए मैंने पहले ही पाया है कि अपील के अधिकार का विनियमन अनुचित होने से बहुत दूर है। इसके अलावा, एक

[5] 1977 पी.एल.जे. 230
[6] आई.एल.आर. 1975 (1) पी.बी. और हरियाणा 89
[7] एआईआर 1977 एस.सी. 915

बार जब यह माना जाता है कि हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 में हरियाणा कानून के बुनियादी प्रावधान संवैधानिक हैं, तो यह कहना शायद ही संभव है कि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के संबंध में केवल सही अपील अपने आप में एक मौलिक अधिकार बन जाएगी या उसी आधार पर उल्लंघन किया जाएगा जिस आधार पर मूल प्रावधानों को चुनौती दी गई है। श्री केपी भंडारी ने हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह किसी ऐसे प्राधिकारी का हवाला नहीं दे सकते जिसमें कहा गया हो कि अपील का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है क्योंकि किसी न किसी बिंदु पर यह दूर से संपत्ति के अधिकार को छूता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के काफी समय की कीमत पर हमारे समक्ष उठाए गए जिज्ञासु विवाद के लिए न तो कोई सिद्धांत है और न ही कोई मिसाल है।

(27) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया एक और दिलचस्प तर्क यह था कि उप-धारा (7) वास्तव में न्यायिक अधिकार क्षेत्र में एक बड़ी घुसपैठ थी। यह तर्क दिया गया था कि यह अपील के लंबित रहने के दौरान भूमि से होने वाले लाभ को निर्धारित करने के लिए विधायिका की ओर से एक अनावश्यक प्रयास था, जो वकील के अनुसार अदालत का एक प्रांत था, न कि कानून निर्माताओं का।

(28) उप-धारा (7) के सादे प्रावधानों के साथ-साथ उस पर पहले रखे गए व्यापक निर्माण को केवल इस विवाद को सरसरी तौर पर नकारात्मक करने के लिए संदर्भ की आवश्यकता है। उपधारा (7) द्वारा विधायिका ने जो किया है, वह तुच्छ अपीलों को हतोत्साहित करने के लिए सुरक्षा का उचित प्रावधान प्रदान करना है और बिना योग्यता के अपील की विफलता पर भूमि के अनधिकृत उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कुछ आश्वासन प्रदान करना है। जैसा कि उपधारा (8) और (9) से स्पष्ट है, राशि को केवल बाद में समायोजित किया जाना है और इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा करने में अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और परिमाणीकरण शामिल है। विधायिका को संभवतः सुरक्षा की मात्रा निर्धारित करने से रोका नहीं जा सकता है जिसे वह तुच्छ अपीलों की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रतिबंध के रूप में व्यापक रूप से आवश्यक मानता है। जब संशोधन के बाद अपील की सफलता और विफलता की स्थिति में क्रमशः उक्त सुरक्षा के रिफंड या समायोजन दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से उपरोक्त तर्क पूरी तरह से सामग्री खो देता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक नहीं बल्कि असंख्य कर विधियों में अपीलीय अधिकार को इस आवश्यकता के साथ बांधा गया है कि अपील पर विचार करने से पहले आकलित कर या उसके भाग को पहले जमा किया जा सकता है। इस संदर्भ में संदर्भ पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 25 या भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 265 के प्रावधानों के लिए किया जा सकता है।

(29) तब यह कहा गया था कि अपीलकर्ता या याचिकाकर्ता से सुरक्षा की मांग करना राज्य के लिए अनुचित था क्योंकि अधिशेष क्षेत्र के मामलों में राज्य स्नातक की किस्तों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य था और इसलिए, अपील की विफलता की स्थिति में उक्त मुआवजे में से लाइसेंस शुल्क की राशि को अच्छी तरह से समायोजित कर सकता था। इस तरह के विवाद को बनाए रखना मुश्किल है। सबसे पहले, यह विधायिका पर निर्भर करता है कि वह राशि की प्रकृति और सुरक्षा के भुगतान के तरीके और तरीके या अपील के अधिकार के विनियमन पर विचार करे जिसे वह आवश्यक समझता है। दूसरे,

अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया जो राज्य को भू-धारकों को देय मुआवजे में से कुछ भी काटने या समायोजित करने का अधिकार देता हो। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि व्यक्ति, जो केवल आवंटी, किरायेदार या अन्यथा अनधिकृत कब्जेदार हैं और जो मुआवजे के हकदार मकान मालिक नहीं हैं, अधिशेष क्षेत्र की घोषणा से व्यथित हो सकते हैं, जिसके खिलाफ वे अपील दायर करना चाहते हैं। अत, ऐसे मामले में भू-धारकों को देय मुआवजे में से लाइसेंस शुल्क के समायोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(30) वकील ने तब तर्क दिया कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 30 का संदर्भ या उस पर भरोसा करना अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। यह बताया गया कि उप-धारा 30 (1) के पहले परंतुक के तहत कर जमा करने की आवश्यकता केवल उसी क़ानून की धारा 46 के तहत चूक से संबंधित थी। यद्यपि इस विवाद में कुछ तथ्य है कि उपर्युक्त धारा 30 द्वारा परिकल्पित निक्षेप पूर्वोक्त सीमित क्षेत्र में संचालित है, यह समान रूप से प्रकट होता है और इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के संबंध में उसमें रखी गई शर्त कम से कम पूर्ण थी और किसी भी अपीलीय प्राधिकारी को छूट देने या नकारात्मक करने का कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया था। उक्त प्रावधान द्वारा अपेक्षित कर जमा करना । इस विवेकाधिकार के अभाव के बावजूद, *अनंत मिल के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में इस तरह के प्रावधान की वैधता का अनुमोदन किया। उपरोक्त मामले को बारीकी से पढ़ने पर, मैं इस विचार से सहमत होने में पूरी तरह से असमर्थ हूं कि निर्णय का वास्तविक अनुपात यह है कि अपील के अधिकार के विनियमन को केवल तभी बरकरार रखा जा सकता है जब व्यक्तिगत मामलों में छूट देने या माफ करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी में एक समान निर्माण निहित हो। जैसा कि मैंने उस फैसले को पढ़ा, अपील के अधिकार के संबंध में टिप्पणियां शर्तों के अनुसार इसे विनियमित करने के लिए लगभग निर्बाध अधिकार को मान्यता देती हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।

(31) अंत में, इस संदर्भ में और भी अधिक उत्सुक तर्क उठाया गया था कि उप-धारा (7) द्वारा आवश्यक सुरक्षा एक कर थी, न कि शुल्क। सच कहूँ तो, मैं कानून की संवैधानिकता के संबंध में दोनों के बीच प्रसिद्ध अंतर के संबंध में एक क्लिच को दोहराने वाले तर्क की पूरी तरह से सराहना करने में असमर्थ रहा हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि धारा 18 की उपधारा (7), (8) और (9) के संदर्भ में कर या शुल्क के बीच अंतर के संबंध में कोई मुद्दा दूर-दूर तक उठता है।

(32) दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं रिट याचिकाओं के इस सेट में कोई योग्यता खोजने में असमर्थ हूं, जिसे मैं इसके द्वारा खारिज करता हूं, जिससे पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(33) हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि रिट, याचिकाकर्ता, जिन्होंने अपील के अपने अधिकार के विनियमन को चुनौती दी थी, मुख्य रूप से निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिशेष क्षेत्र की घोषणा से व्यथित थे। रिट याचिकाओं को खारिज करने से अधिनियम की धारा 18 (1) और (2) द्वारा उन्हें प्रदान की गई अपील और संशोधन के माध्यम से उपाय का सहारा लेने के उनके कानूनी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, वे सभी

अपने सामान्य वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं यदि वे किसी व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के मामले में आकर्षित होते हैं।

एस. एस. दीवान, जे. मैं *सहमत हूं।*

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी